



# भारत का राजपत्र

## The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)  
PART II—Section 3—Sub-section (ii)  
प्राधिकार से प्रकाशित  
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2287]

नई दिल्ली, बुधवार, नवम्बर 3, 2010/कार्तिक 12, 1932

No. 2287]

NEW DELHI, WEDNESDAY, NOVEMBER 3, 2010/KARTIKA 12, 1932

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 4 नवम्बर, 2010

का.आ. 2707(अ).—यतः केन्द्रीय सरकार ने, सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 (1958 का 28) की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, सम्पूर्ण असम राज्य को दिनांक 27-11-1990 की अधिसूचना का.आ. 916(अ) के तहत दिनांक 27-11-1990 से 'विशुद्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः, केन्द्रीय सरकार ने पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 3 द्वारा प्रदत्त शक्तियों को प्रयोग करते हुए, अन्य क्षेत्रों के अतिरिक्त असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्रों को भी 'विशुद्ध क्षेत्र' के रूप में घोषित किया था।

और यतः, इस घोषणा को, कि असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्य में सीमा से 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र उक्त अधिनियम के अंतर्गत 'विशुद्ध क्षेत्र' रहेंगे, असम राज्य तथा पूर्वोक्त क्षेत्रों में कानून एवं व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा करने के बाद, समय-समय पर बढ़ाया गया था।

और यतः, असम राज्य तथा असम राज्य की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों में 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में कानून एवं व्यवस्था की आगे और समीक्षा करने से निम्नलिखित इंगित होता है:

- (i) भूमिगत संगठनों द्वारा की आने वाली हिंसक घटनाओं के कारण असम राज्य में कानून और व्यवस्था की स्थिति चिंता का विषय बनी हुई है।

- (ii) जनवरी से सितम्बर, 2010 तक की अवधि के दौरान भूमिगत संगठन असम में हिंसा की 196 घटनाओं में शामिल थे जिनके परिणामस्वरूप 12 सुरक्षा कर्मियों सहित 41 व्यक्तियों की मृत्यु हो गई।

- (iii) इस क्षेत्र में सक्रिय उग्रवादी संगठनों का विश्वास सशस्त्र संघर्ष में कायम है तथा ये आम जनता में डर पैदा करने, प्रशासनिक प्रणाली को अस्त-व्यस्त करने तथा जनता से जबरन धन वसूली करने के लिए हिंसा के कृत्यों में संलिप्त हैं।

- (iv) अरुणाचल प्रदेश के अंदर 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी में आने वाले क्षेत्रों, विशेष रूप से तीरप चांगलांग, लोहित, पूर्वी एवं पश्चिमी सियांग और निचली दिबांग घाटी के जिलों में उग्रवादी गतिविधियों के कारण कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। अरुणाचल प्रदेश और मेघालय से लगे असम के सीमावर्ती क्षेत्रों में उग्रवादी गतिविधियों की भरमार रही है। उग्रवादियों द्वारा सीमावर्ती गांवों में जबरन धन वसूली की गतिविधियां चलाया जाना जारी है। ब्लॉक-1 क्षेत्र (असम मेघालय सीमा पर विवादित क्षेत्र/जैतिया हिल्स जिला) में सक्रिय यूनाइटेड पीपल्स डेमोक्रेटिक सौलिवेरीटी (यू पी डी एस) के उग्रवादी नार और नेपाली आधिपत्य वाले गांवों अर्थात् नॉनग्रॉंग मिन्जू, अम्बासू, सार, मोल्लाबेर, मूरप आदि (सभी नार गांव) से तथा कोलालफंग और मोजोंग (नेपाली गांव) से कथित रूप से आवास कर की मांग भी करते रहे हैं। छोटे किसानों से भी उनके कृषि उत्पादों की बिक्री से प्राप्त राशि की जबरन वसूली की जा रही है।

अतः अब, सम्पूर्ण असम राज्य तथा असम की सीमा से लगे अरुणाचल प्रदेश और मेघालय राज्यों की 20 कि.मी. चौड़ी पट्टी के अंतर्गत आने वाले क्षेत्र सशस्त्र बल (विशेष शक्तियाँ) अधिनियम, 1958 की धारा 3 के अंतर्गत एक वर्ष तक 'विशुद्ध क्षेत्र' बने रहेंगे जब तक कि इस धारा को इससे पहले हटा न लिया जाए।

[फा. सं. 11011/38/98-एन.ई.-IV]

शम्भू सिंह, संयुक्त सचिव

## MINISTRY OF HOME AFFAIRS

### NOTIFICATION

New Delhi, the 4th November, 2010

**S.O. 2707(E).**—Whereas the Central Government in exercise of powers conferred by Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 (28 of 1958) had declared the entire State of Assam as 'disturbed area' with effect from 27-11-1990 *vide* Notification S.O. 916(E), dated 27-11-1990.

And whereas the Central Government in exercise of power conferred by Section 3 of the aforesaid Act had also declared besides other areas, the areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam as 'disturbed area'.

And whereas the declaration that the State of Assam and areas falling within 20 kms wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya along their border with the State of Assam shall be 'disturbed area' under the aforesaid Act was extended from time to time after reviewing the law and order situation in the State of Assam and aforesaid areas.

And whereas a further review of the law and order situation in Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam indicates the following :—

- (i) The law and order situation in the State of Assam has continued to be a matter of concern due to the violent incidents by underground outfits.

- (ii) During the period January to September 2010, the Under Ground Outfits were involved in 196 incidents of violence in Assam which resulted in killings of 41 persons including 12 security personnel.
- (iii) The militant outfits operating in the area continue to affirm their faith in armed struggle and indulge in acts of violence to create panic among the common people, disturb the administrative system and extort from the people.
- (iv) The areas falling in the 20 kms. wide belt inside Arunachal Pradesh have witnessed deterioration in law and order due to militant activities in the districts of Tirap, Changlang, Lohit, East and West Siang and Lower Dibang Valley districts. The bordering areas of Assam with Arunachal Pradesh and Meghalaya have remained infested with by militant activities. Militants continue to carry out extortion activities in the bordering villages United Peoples Democratic Solidarity (UPDS) militants (a Karbi Anglong/Assam based militant outfit), operating in Blok-1 area (disputed area in Assam-Meghalaya border/Jaintia Hills district) have also been reportedly demanding house-tax from Pnar and Nepali dominated villages viz. Nongrang, Mynju, Umbasoo, Psiar, Mollaber, Murap etc. (all Pnar villages) and Kolalaphang and Mojong (Nepali villages), Petty farmers are also being extorted of the sale proceeds of agricultural products.

Now, therefore, the entire State of Assam and 20 kms. wide belt in the State of Arunachal Pradesh and Meghalaya bordering Assam shall continue to be 'disturbed area' under Section 3 of the Armed Forces (Special Powers) Act, 1958 upto one year unless withdrawn earlier.

[F. No. 11011/38/9-NE-IV]

SHAMBHU SINGI, Jt. Secy.